भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3291

दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

3291. श्री मितेश पटेल बकाभाई:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन देशों की संख्या कितनी है, जिनके साथ भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डी.पी.आई.) के लिए समझौता ज्ञापनों या सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन–से हैं;

(ख) ऐसे सभी समझौतों का मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) साझेदार देशों में भारत के डिजिटल सार्वजनिक सामान की तैनाती और क्षमता–निर्माण पहलों सहित इन समझौतों के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) डी.पी.आई. साझेदारियों के साझेदार देशों और संबंधित मंत्रालयों तथा एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए क्या संस्थागत ढांचा अपनाया गया है; और

(ङ) अगले तीन वर्षों के लिए विशेषकर ग्लोबल साउथ के देशों के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के अंतरराष्ट्रीय सहयोग के विस्तार का रोडमैप क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) संबंधी फ्रेमवर्क अंतर–सरकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) जिसका शीर्षक "डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर लागू सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के

क्षेत्र में सहयोग" है, पर अब तक 24 देशों के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और इंडिया स्टैक प्रौद्योगिकी समाधानों के आदान–प्रदान को सुगम बनाया जा सके।

(ख) डीपीआई संबंधी फ्रेमवर्क समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक कार्मिकों के लिए क्षमता निर्माण, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान–प्रदान, पायलट समाधानों का विकास, निजी क्षेत्र के संपर्कों की सुविधा आदि के माध्यम से भागीदार देशों के लाभ के लिए डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाना है।

(ग) सरकार नियमित रूप से सहयोगी देशों के प्रतिनिधिमंडलों के लिए अध्ययन यात्राओं और तकनीकी संवाद की सुविधा प्रदान करती है। इससे वे भारत में प्रमुख डीपीआई संस्थानों, जैसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेशनल ई–गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) आदि के साथ जुड़ पाते हैं। इन सहभागिताओं से सहयोगी देशों को अपने डीपीआई विकसित करने में भारत के अनुभव का लाभ उठाने और डीपीआई समाधानों के लिए सहयोग के अवसरों व कार्यान्वयन के तरीकों पर चर्चा करने में मदद मिलती है। हाल की कुछ यात्राओं में श्रीलंका, केन्या, रवांडा, नेपाल, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित डीपीआई–आधारित परियोजनाएं वर्तमान में श्रीलंका, म्यांमार, केन्या और गुयाना में लागू की जा रही हैं; साथ ही मॉरीशस और सेशेल्स के साथ डीपीआई परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ और ङ) डीपीआई संबंधी सहयोग का रोडमैप, संबंधित भागीदार देशों के साथ घनिष्ठ परामर्श करके तैयार किया जाता है, क्योंकि भारत का विकास सहयोग मॉडल मांग–संचालित है और भागीदार देशों की जरूरतों, प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप है। सहयोगी देशों के साथ अलग–अलग डीपीआई समाधानों को अंतिम रूप देने का काम उनके नामित प्राधिकारियों के साथ तकनीकी चर्चाओं के माध्यम से किया जाता है, जिसके लिए संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों के प्रतिनिधियों को आवश्यकतानुसार भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

*****